जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 13 संख्याः 302 प्रभात चूरू, मंगलवार 1 मार्च, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

अमेरिका के अधिकांश स्टेट्स में ग्रे वुल्फ फिर से संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। गौर तलब है कि ट्रम्प प्रशासन ने इसे दुर्लभ जीवों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। अब एक फैडरल जज ने इस फैसले को पलट दिया है और एन्डैन्जर्ड स्पीशीज़ के तहत ग्रे वुल्फ के लिए संरक्षण बहाल कर दिया है। अर्थ जस्टिस नामक संस्था ने सिएरा क्लब और ह्यूमेन सोसायटी सहित कई संस्थाओं की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत यह फैसला आया है। इस फैसले के तहत 44 राज्यों में भेड़ियों को संरक्षण दिया गया है। तथापि, आइडाहो, मोन्टाना एवं वायोमिंग सहित नॉर्दर्न रॉकीज़ में इस रूलिंग के तहत वुल्फ को पुनः संरक्षण नहीं मिल सका है। फैसले पर खुशी जताते हुए ह्यूमेन सोसायटी की अध्यक्ष व सी.ई.ओ. किटी ब्लॉक ने कहा कि "फैडरल कोर्ट के इस निर्णय बाद फिश एण्ड वाइल्ड लाइफ सर्विस को अंततः सबक सीख जाना चाहिए। जंगली जानवरों से कानूनी संरक्षण वापस लेने के लिए पेचीदे बहाने बनाने के बजाय एजेंसी को इस प्रजाति की रेंज की सार्थक रिकवरी की योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रे वुल्फ की आबादी घटे नहीं।" ग्रे वुल्फ को सन् 1974 में एन्डेन्जर्ड स्पीशीज़ करार दिया गया था, क्योंकि ये जीव यू.एस. के मुख्य भू भाग से लगभग लुप्त हो गए थे। फिर कैनेडियन ग्रे वुल्फ के जरिए इन्हें पुनः लाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और इसके बाद ग्रे वुल्फ कैनेडा के नॉर्दन रॉकीज़ और वैस्टर्न ग्रेट लेक में खूब फले-फूले। इंटरनैशनल यूनियन फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन.) की रैड लिस्ट में इन भेड़ियों को "लीस्ट कन्सर्न" वर्ग में रखा गया है। ग्रे वुल्फ को "एन्डेन्जर्ड" वर्ग में रखा जाए या नहीं इस मुद्दे पर संरक्षण समूहों और यू.एस. फिश एण्ड वाइल्ड लाइफ सर्विस के बीच लंबे समय तक काफी चर्चा हुई। सन् 2020 में जब इन्हें संरक्षण लिस्ट से हटाया गया था तब भी भारी विरोध हुआ था। अठारह लाख लोगों ने ऑन लाइन विरोध जताया था। संरक्षण हटने के बाद विस्कॉन्सिन में, फरवरी 2021 में वुल्फ के शिकार का आयोजन हुआ जिसमें शिकारियों ने तीन दिन में ही 218 भेड़िए मार दिए, जो निर्धारित कोटा से 100 अधिक थे।

असर दिखाने लगी है "इकोनॉमिक पाबंदियों" की नीति

राष्ट्रपति पुतिन ने "इकोनॉमिक पाबंदियों" को गैर कानूनी बताया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। रूस को स्विफ्ट (एस.डब्ल्यु.आई.एफ.टी.) व्यवस्था से बाहर निकाल दिया गया है। यह एक तरह से बैंकों का ग्लोबल जी मेल नैटवर्क है ताकि फंड्स का लेन देन सुरक्षित तरीके से हो सके। इस नैटवर्क से निकाले जाने का अर्थ है कि रूसी बैंक अन्य बैंकों के साथ सामान्य लेन देन नहीं कर पाएंगे।

दबाव में आए रूसी राष्ट्रपति व्यादीमिर पुतिन ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंध अवैध हैं। इन प्रतिबंधों ने रूस को परेशान करना शुरू कर दिया है और वहां गंभीर वित्तीय दबाव है।

यह पहली बार है जब "जिओ-इकोनॉमिक्स" (भौगोलिक-आर्थिक) एक महत्वपूर्ण एवं ताकतवर युद्ध हथियार के रूप में उभरा है। यूरोपियन यूनियन रूस पर दबाव बनाने के लिए बड़ी निष्ठुरता से हथियार का प्रयोग कर रहा है।

इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि रूस शेष विश्व के साथ व्यापार व वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं कर पाएगा। इसे अपने सारे प्रमुख निर्यात, जिनमें तेल व गैस प्रमुख है, का भुगतान नहीं मिल पाएगा, ना ही रूस अन्य देशों से आयात के लिए भुगतान कर पाएगा। रूस पूरी तरह से अलग-थलग हो गया है। इससे पहले सिर्फ एक देश इरान को स्विफ्ट से निकाला गया था, जब उसने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, वो दिन इरान के सबसे बुरे दिन थे। इसकी वजह से इरान के व्यापार में एक तिहाई की कमी आई थी।

इसी के साथ यूरोपियन सैन्ट्रल बैंक ने रशियन सैन्ट्रल बैंक के विदेशी संसाधन फ्रीज कर दिए हैं। रूस के पास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम "स्विफ्ट" से वंचित होने के कारण रुस अपने निर्यात (मुख्यतया ऑयल व गैस) के बेचान से मिलने वाली राशि को अपने देश में "बैंक ट्राज़ैक्शन" के मार्फत नहीं ले जा पायेगा, और फिर धन के अभाव में वह आयात की गयी सामग्री का भुगतान भी नहीं कर पायेगा। ऐसी सख्त पाबंदियां पहले केवल एक बार लगी हैं "ईरान" पर न्युक्लियर हथियार बनाने के मामले में और कुछ ही समय में ईरान के व्यापारिक कामकाज में 33 प्रतिशत की गिरावट आ गयी थी।
- रुस को आशा थी कि 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भण्डार, जो उसने इकट्ठा कर रखा था, वह व्यापारिक कामकाज की दिक्कतों से उसे उबार देगा। पर यूरोपियन सैन्ट्रल बैंक ने रुस के सैन्ट्रल बैंक का खाता भी "सीज़" कर दिया है, अतः 630 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा भी रुस के काम नहीं आ सकेगी।
- इन्हीं कारणों से रुस की मुद्रा, रुबल का तीस प्रतिशत अवमूल्यन हो गया है तथा ब्याज़ दर 20 प्रतिशत हो गयी है। स्टॉक मार्केट में भारी आशंका के कारण रुस के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने आज कारोबार स्थगित कर दिया।
- रुस में लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हैं, ए.टी.एम. व बैंक दफ्तरों के सामने पैसा निकालने के लिए। बैंकों के प्रबंधन ने सीमा बांधी, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी राशि निकाल सकता है।
- रुस को चीन से मदद की आशा थी पर अभी तक कुछ मदद नहीं मिली, चीन अभी तक सभी पाबंदियों का अनुपालन कर रहा है।

चुनाव के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर होगी

टी.एस. सिंह देव कई दिनों से दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं तथा भारी लॉबीइंग चल रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद, छत्तीसगढ़ में राजनैतिक गहमागहमी के विस्फोटक रूप लेने के आसार दिखाई दे रहे हैं। टी.एस. सिंह देव दिल्ली में नेताओं से मिलकर, भूपेश बघेल को हटाने के लिये लामबंदी कर रहे हैं तथा खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आग्रह कर रहे हैं।

इस लामबंदी का एक बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी ने सिंह देव उर्फ बाबा (जिस नाम से वे जाने जाते हैं) से वादा किया था कि विधानसभा चुनावों के बाद, उन्हे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा।

- सिंह देव बार-बार सबको याद दिला रहे हैं कि, स्वयं राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मु.मंत्री बनाया जायेगा।
- पर सिंह देव की मु.मंत्री की दौड़ में सबसे बड़ी बाधा, उनके अनुसार प्रियंका गांधी हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही बघेल को बचाया जब राहुल गांधी उन्हें हटाने का निर्णय ले चुके थे।
- साथ ही प्रियंका गांधी ने बघेल को यूपी के चुनाव में अपने साथ रखा व आर्थिक मदद भी प्राप्त की।
- राजस्थान में भी लगभग यह ही स्थिति है, जहां गहलोत को हटाने की चर्चा जोरों पर है। पर वे बघेल की भांति हटेंगे तभी, जबकि राहुल व प्रियंका इस मुद्दे पर एकमत होंगे।

बाबा पार्टी नेताओं से कह रहे हैं कि वे इस मुद्दे को जोर-शोर से उठायेंगे, हो-हल्ला करेंगे तथा तब तक आराम से नहीं बैठेंगे, जब तक राहुल गांधी अपना वादा पूरा नहीं करते।

एक समस्या, जो बाबा के रास्ते की एक बड़ी बाधा बन सकती है, स्वयं प्रियंका गांधी है, जो बघेल की सबसे बड़ी समर्थक एवं पक्षधर रही हैं। प्रियंका ने उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार के लिये अपने साथ रखा हुआ है ताकि बघेल प्रियंका को आर्थिक मदद के साथ, अन्य प्रकार का सहयोग-समर्थन देते रहे।

पिछली बार, जब राहुल गांधी बघेल को, ढ़ाई साल मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद, बदलना चाहते थे, उस समय भी प्रियंका ने ही उनका पद बचाया था।

यही स्थिति राजस्थान में होने की संभावना है, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी दाँव पर लगी हुई है। कल गहलोत और बघेल दोनों ही दिल्ली में थे तथा दोनों की राहुल तथा प्रियंका के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में वेणुगोपाल भी मौजूद थे। अगर राहुल और प्रियंका एकमत हो जायें, जो संभावना के नियम के विपरीत-जैसा है, तो कोई भी नेतृत्व परिवर्तन संभव हो सकता है।

'मान प्रतिष्ठा का सवाल'

-जाल खंबाता
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमन्ना की अध्यक्ष वाली बैंच सोमवार को इस बात पर सहमत हो गयी कि टाटा ग्रुप के साथ उनके विवाद के सिलसिले में सायरस मिस्त्री द्वारा दायर की गयी याचिका की सुनवाई 10 दिन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- साइरस मिस्त्री, जिन्हें कुछ समय के लिए टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी बनाया गया था, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय उनके खिलाफ जो टिप्पणियां की, उससे उनकी "मान प्रतिष्ठा" को आघात पहुंचा है, अतः उन्हें निर्णय से अलग किया जाए।

यूरोप बदल गया यूक्रेन पर आक्रमण के बाद

कई देश, विशेषकर जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, "सैन्यकरण" नहीं करने की कसम खायी थी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। यूक्रेन पर रूस के हमले ने अब यूरोप को सदा के लिए बदल दिया है। यूरोप एक बार फिर सैन्य रूप से सुसज्जित हो रहा है और पुनः युद्ध की दहलीज पर है।

रूसी हमले ने यूरोप के रंग-ढंग को बदल दिया है और यह रूपान्तर ऐसा हुआ है, जैसार रूस बिल्कुल नहीं चाहता था। यूरोप को अपने सहयोग को लेकर नाटो और अधिक मजबूत हुआ है तथा यूरोपीयन यूनियन (ई.यू.) के देश राजनीतिक रूप से और निकट आ गए हैं।

ई.यू. फॉरेन पॉलिसी के बड़े प्रतिनिधियों ने रूस की चुनौती से निपटने के नुकसान व खर्चों को लेकर बात की है। रूस पूर्वी यूरोप के देशों को बलपूर्वक अपने में मिला रहा है या परमाणु हमले की धमकी देकर इन देशों में अपनी कठपुतली सरकारें बना रहा है। लगता है कि ई.यू. ने यूरोप की भविष्य की सरकारों को सुरक्षित करने को लेकर संभावित परमाणु हमले की चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत जुटा ली है। इसके साथ ही, ई.यू. रूस की जनता से सीधे अपील कर रहा है और चाहता है कि वहां की आम जनता स्वयं को पुतिन के शासन से अलग कर ले।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पर यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने अपनी सेना बढ़ाने व उसे आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित करने की योजना बनाई है।
- जर्मनी, यूरोप का सबसे धनाढ्य व सुव्यवस्थित देश है और उसके "सैन्यकरण" के इस निर्णय से कई और छोटे-छोटे देश अपनी-अपनी सेना मजबूत करने की सोचने लगे हैं।
- रुस की "न्यूक्लियर वॉर" की धमकी को भी रुस के हताश होने का लक्षण माना जा रहा है।
- क्या यूक्रेन आक्रमण से वो हुआ, जो रुस कतई नहीं चाहता था, कि यूरोप के छोटे-छोटे देश उसके खिलाफ संगठित होने का साहस दिखाएं।

जाली नोट

निम्बाहेड़ा, 28 फरवरी (निसं)। थाना सदर निंबाहेड़ा पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने सोमवार को थाना अंतर्गत मंडला गांव के एक रिहायशी मकान में दबिश देकर 500 एवं 100 रुपये के नकली नोट बनाने के उपकरण जब्त कर 3 लाख 48 हजार 3 सौ रुपयों की जाली मुद्रा पकड़ी है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

चित्तौड़गढ़ एसपी प्रीति जैन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में नकली नोट प्रचलन की शिकायत प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

- 3.48 लाख रु. के जाली नोट बरामद, दो अभियुक्त गिरफ्तार।

कैलाश सिंह सांन्दू के निर्देशन में नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में सोमवार को डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह राणावत को सूचना मिली कि थाना निम्बाहेड़ा सदर अंतर्गत मण्डला गांव में किशन दान चारण नाम के व्यक्ति के घर नकली करेंसी बनाने का कारोबार चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर थानाधिकारी फूल चन्द टेलर व डीएसटी प्रभारी विक्रम राणावत के नेतृत्व में टीम गठित की जाकर किशन दान चारण के मकान में दबिश दी गई।

पुलिस ने मौके से किशन दान पुत्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक साथ दो युद्ध लड़े जा रहे हैं यूक्रेन में

एक युद्ध हथियारों व टैंक्स से लड़ा जा रहा है, दूसरा डिजिटल युद्ध सोशल मीडिया में हो रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। अपने ग्राहकों को लुभाने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापारिक फर्में ही अब तक विकास के ऑनलाइन व ऑफलाइन मॉडल का उपयोग करती रही हैं, लेकिन यह मॉडल अब इस परम्परागत दायरे से बाहर निकलकर देश की सेना के शस्त्रागार का एक अभिन्न अंग बन गया है।

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। वर्तमान युद्ध में किया जा रहा यह प्रयास स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इन्टरनैट के माध्यम से गलत जानकारी देकर जनमानस को बदला जा रहा है और यह माध्यम भी वास्तविक सेना व हथियारों के साथ युद्ध का संचालन कर रहा है।

एसोसिएटेड प्रैस (ए.पी.) की एक रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न अनुसंधान संगठनों के विश्लेषकों ने सम्पर्क करने पर बताया कि उन्हें रूस से सम्बद्ध समूहों की ऑनलाइन गतिविधि में भारी इजाफा नज़र आ रहा है। ऐसा रूस की रणनीति के अनुरूप चलने के लिए किया जा रहा है। वह अपनी इस रणनीति के तहत पश्चिमी गठबंधन को कमजोर करने के साथ ही घरेलू मीडिया और सरकारी प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहा है।

गलत जानकारी का पता लगाने के काम में लगी एक इज़रायली टैक कंपनी, "सायब्रा" की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्टरनैट पर यूक्रेन विरोधी संदिग्ध सामग्री परोसने वाले अकाउन्ट्स की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफ़ा हुआ है।

सायब्रा के विश्लेषकों ने फेसबुक और ट्विटर के ऐसे हजारों अकाउन्ट्स को ट्रैक किया, जिन्होंने हाल ही में यूक्रेन को लेकर पोस्ट डाली थी। उन्होंने हमले के ठीक पहले के दिनों में यूक्रेन विरोधी सामग्री में एक आकस्मिक व नाटकीय बढ़ोतरी नोट की। मिसाल के तौर पर, वैलेन्टाइन डे के कुछ दिन पूर्व की तुलना में यूक्रेन विरोधी पोस्ट डालने वले ट्विटर अकाउन्ट्स की संख्या 11,000 प्रतिशत बढ़ गई। विश्लेषकों का मानना है कि इनमें से बहुत सारे अकाउन्ट्स अप्रमाणित थे एवं रूसी सरकार से सम्बद्ध ग्रुप्स द्वारा नियंत्रित हैं।

सायब्रा के सी.ई.ओ. डैन ब्राह्मी कहते हैं कि "जब आप 11,000 प्रतिशत का इजाफा देखते हैं, तो समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई नहीं जानता कि पर्दे के पीछे ये सब कुछ कौन कर रहा है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं।"

एटलांटिक काउन्सिल के डिज़िटल फोरैन्सिक, रिसर्च लैब के अनुसंधानकर्ताओं ने सरकार के स्वामित्व वाले रूस के 10 समाचार केन्द्रों के 3 हजार लेखों का अध्ययन कर यह जाना कि इन निराधार दावों में एक बड़ा इजाफा हुआ कि "यूक्रेन अलगाववादी गुटों पर हमले करने वाला है।" अनुसंधान के अनुसार यूक्रेन के आक्रमण को लेकर रूसी मीडिया के दावे में गत जनवरी माह में ही कुल मिलाकर 50 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ।

अमेरिका के पूर्व रक्षा विश्लेषक एवं वर्तमान में साल्वे रेज़िना युनिवर्सिटी में पैल सैन्टर फॉर इन्टरनैशनल रिलेशन्स एण्ड पब्लिक पॉलिसी के निदेशक जिम ल्यूड्स ने कहा कि "यह युद्ध छेड़ने का उनका एक तरीका है। यह रूसी सिद्धांत का मुख्य भाग है।" उन्होंने कहा कि रूस के भ्रामक जानकारियों वाले प्रचार अभियानों का उद्देश्य अपने विरोधियों को विभाजित और भ्रमित करने के साथ ही अपने लिए समर्थन जुटाना होता है।

यू.एस. काउन्टरटैरेज़िम सैन्टर के स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल प्लानिंग के एक पूर्व निदेशक एवं सेना के सेवानिवृत्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ऐसा माना जा रहा है, कि "सोशल मीडिया" का युद्ध ज्यादा प्रभावी है और लम्बे समय तक असर डालता है।
- एसोसिएटेड प्रैस द्वारा प्रसारित एक रिपोर्ट के अनुसार, रुस से संचालित ट्विटर व फेसबुक एकाउन्ट्स की गतिविधियों में 11,000 गुना तक वृद्धि हुई, यूक्रेन पर आक्रमण से पहले।
- रुस के मीडिया ने यह विश्वास जमाने का प्रयास किया कि, यूक्रेन की तरफ से शीघ्र ही आक्रमण होने वाला है। तथा युक्रेन सैपरेटिस्ट तत्वों, (अलगाववादी), संगठनों व व्यक्तियों पर भी गोले बरसायेगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार इस डिस्इन्फॉर्मेशन अभियान का लक्ष्य है रुस के अंदर युद्ध के लिए समर्थन बढ़ाना तथा पश्चिमी देशों के गठबंधन में "अस्थिरता" व कन्फ्यूज़न पैदा करना।

धारीवाल ने यूक्रेन फोन पर बात की

कोटा, 28 फरवरी (निसं)। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने यूक्रेन में रह कर एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई कर रही कोटा की हिमांशी सैनी से स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सोमवार को मोबाइल पर वार्ता कर वहां के हालातों की जानकारी ली। उन्होंने राजस्थान सरकार के प्रयासों की जानकारी देकर आश्वस्त किया कि उन्हें

- यूक्रेन में पढ़ रहे कोटा के मूल निवासी छात्रों का मनोबल बढ़ाया धारीवाल ने।

सकुशल घर तक लाया जायेगा।

स्वायत्त शासन मंत्री जन सुनवाई कर रहे थे जैसे ही दूरभाष पर उन्हें कोटा के कुन्हाड़ी निवासी सी.एस. सैनी की बेटी के यूक्रेन की राजधानी कीव में होने की जानकारी मिली तो वीडियो कॉल कर हिमांशी व परिजनों से वार्ता की और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सभी बच्चों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)